

नजिता का अधिकार

प्रलिस के लयः

के.एस. पुट्टस्वामी मामला, अनुच्छेद 21, नजिता के अधिकार के वभिन्न आयाम ।

मेन्स के लयः

के.एस. पुट्टस्वामी मामला, नजिता का अधिकार, अनुच्छेद 21, व्यक्तगत डेटा संरक्षण वधियक 2019 ।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **मद्रास उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश** ने कहा है कि उसी अदालत के एक अन्य न्यायाधीश द्वारा हाल ही में पारित एक आदेश जिसमें सपा [मालिश और चकितिसा केंद्र] के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाने को अनविरय कया गया है, सर्वोच्च न्यायालय के ऐतहासिक फैसले **के.एस पुट्टस्वामी मामला (2017)** के वपिरत प्रतीत होता है ।

- इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह घोषणा की थी कि **अनुच्छेद 21** में गारंटीकृत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में नजिता का अधिकार भी शामिल है ।

प्रमुख बडि

परचयः

- **अंतरनहिति मूल्यः** नजिता के इस अधिकार को मूल अधिकार के रूप में देखा जाता है:
 - **नहिति मूल्य (Inherent value):** यह प्रत्येक व्यक्त की मूल गरमा के लय महत्त्वपूर्ण है ।
 - **वाद्य मूल्य (Instrumental value):** यह किसी व्यक्त के हस्तक्षेप से मुक्त जीवन जीने की क्षमता को आगे बढाता है ।
- **नजिता के अधिकार के रूपः** अनुच्छेद 21 में गारंटी के रूप में नजिता कई अलग-अलग रूप में शामिल हैं:
 - दैहिक स्वतंत्रता/शारीरिक स्वायत्तता का अधिकार
 - सूचनात्मक गोपनीयता का अधिकार
 - पसंद का अधिकार ।
- **आराम करने का अधिकार/राईट टू रलैकसः** यह संदेह कि 'सपा' में अनैतिक गतविधियों हो रही हैं, किसी व्यक्त के आराम करने के अधिकार में दखल देने का पर्याप्त कारण नहीं हो सकता, क्योंकि यह **आंतरिक रूप से उसके मौलिक अधिकार (नजिता के अधिकार) का हसिसा** है ।
 - इस प्रकार, सपा जैसे किसी परसिर के भीतर सीसीटीवी उपकरण की स्थापना नसिंसेह किसी व्यक्त की **दैहिक स्वतंत्रता के खलिफ** होगी ।
 - ये **अनुलंघनीय** स्थान हैं जहाँ राज्य सरकार को नज़र रखने की अनुमत नहीं दी जा सकती
- **शक्तियों के पृथक्करण का सदिधांतः** किसी भी न्यायिक उपाय के ज़रयि मौलिक अधिकारों की पहुँच को कम नहीं कया जा सकता है ।
 - इस सदिधांत के तहत यह माना गया है कि, यद्यपि कोई अधिकार पूर्ण नहीं हो सकता है इसलिये केवल वधायिका या कार्यपालिका द्वारा ही प्रतबंध लगाए जा सकते हैं ।
 - इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय अकेले ही **अनुच्छेद 142** के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करके ऐसा कर सकता है ।

नजिता का अधिकार

परचयः

- आमतौर पर यह समझा जाता है कि गोपनीयता **अकेला छोड़ दये जाने के अधिकार (Right to Be Left Alone)** का पर्याय है ।
- सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2017 में के.एस. पुत्तास्वामी बनाम भारतीय संघ ऐतहासिक नरिणय में गोपनीयता और उसके महत्त्व को वर्णति कया । सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, नजिता का अधिकार एक मौलिक और अवच्छेद्य अधिकार है और इसके तहत व्यक्त से जुड़ी सभी

सूचनाओं के साथ उसके द्वारा लिये गए नरिणय शामिल हैं।

- नजिता के अधिकार को **अनुच्छेद 21** के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के आंतरिक भाग के रूप में तथा संवधान के भाग-III द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता के हस्से के रूप में संरक्षित किया गया है।

■ **प्रतर्बिंध (नरिणय में वरणति):**

- इस अधिकार को केवल राज्य कार्रवाई के तहत तभी प्रतर्बिंधति किया जा सकता है, जब वे नमिनलखिति तीन परीक्षणों को पास करते हों :
 - पहला, ऐसी राजकीय कार्रवाई के लिये एक **वधायी जनादेश** होना चाहिये;
 - दूसरा, इसे एक **वैध राजकीय उद्देश्य** का पालन करना चाहिये;
 - तीसरा, यह **यथोचित होनी चाहिये**, अर्थात् ऐसी राजकीय कार्रवाई- प्रकृति और सीमा में समानुपाती होनी चाहिये, एक लोकतांत्रिक समाज के लिये आवश्यक होनी चाहिये तथा किसी लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु उपलब्ध विकल्पों में से सबसे कम अंतर्वेधी होनी चाहिये।

- **नजिता की सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदम:** नजिता के महत्त्व को स्वीकार करते हुए सरकार ने **व्यक्तिगत डेटा संरक्षण वधियक 2019** को संसद में पेश किया है।

स्रोत: द हट्टि

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/right-to-privacy-4>

